

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06.01.2014

कि.नि.पु. 5/2014

नरेंद्र कुमार जैन

.....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री गणेश कुमार, शर्मा, अधिवक्ता

बनाम

आर.एस. सेवक

....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री जी.बी. सेवक, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी

न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी (खुला न्यायालय)

1. यह दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 ("अधिनियम") की धारा 25-ख के तहत दायर एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें विद्वान अति.सि.न्या.-सह-वाणि.सि.न्या.-सह-अति.कि.नि.(पूर्व), कड़कड़डूमा न्यायालय ("आक्षेपित आदेश") के 9 सितंबर, 2013 के आदेश को चुनौती दी गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा, विद्वान अति.कि.नि. ने याचिकाकर्ता-किरायेदार ("किरायेदार") के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें बचाव के लिए अनुमति मांगी गई थी और 2012 के बेदखल

याचिका सं. ई-113 में किरायेदार के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था।

2. विवाद का पता प्रत्यर्थी-मकान मालिक ("**मकान मालिक**") द्वारा विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष दायर एक बेदखली याचिका से लगाया जा सकता है, जिसमें मकान मालिक ने किरायेदार को उसकी सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर वाद संपत्ति- एक दुकान- से बेदखल करने की मांग की थी। मकान मालिक का मामला, जो स्वयं लगभग 80 वर्ष की आयु का एक अधिवक्ता था, यह था कि उसे अपने बेटे - जो 2004 से वकील है - के लिए वकालत चैंबर स्थापित करने के लिए इस वाद संपत्ति की आवश्यकता थी। मकान मालिक द्वारा स्वीकार किया कि वाद संपत्ति के अलावा उसकी एक और दुकान थी, जो दुकान संख्या 2 से सटी हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि, उक्त दुकान केवल 6 'x 10' की है और एक चैंबर स्थापित करने के लिए उपयुक्त नहीं होगी। मकान मालिक ने वाद संपत्ति और दुकान सं. 2 के बीच की दीवार को हटाने और 12' x 10.3' के बड़े स्थान को अपने बेटे के लिए चैंबर के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था। विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष शपथपत्र में कहा गया कि बेटे के पास कोई अन्य चैंबर नहीं है।
3. किरायेदार ने विभिन्न आधारों पर याचिका का बचाव करने की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन दायर किया, जिस पर इस न्यायालय को

वर्तमान मामले में विचार करने की आवश्यकता नहीं है; पुनरीक्षण में चुनौती उन निष्कर्षों के आधार पर नहीं है। वर्तमान वाद में, विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष यह प्रतिवाद दिया गया था कि मकान मालिक की आवश्यकता सद्भावनापूर्ण नहीं थी और मकान मालिक सत्य के गोपन और असत्य का सुझाव देने में लिप्त था क्योंकि यह अकल्पनीय है कि मकान मालिक का बेटा एक चेंबर के बिना काम कर सकता था। यह भी प्रतिवाद दिया गया कि मकान मालिक के पास पहले से ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसमें से उसका बेटा अपने चेंबर का संचालन कर सकता था और इसलिए यह दावा कि उस उद्देश्य के लिए वाद संपत्ति की आवश्यकता थी, सद्भावनापूर्ण नहीं है। अंत में, यह प्रतिवाद किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद एक चेंबर के बिना काम किया है और तीस हजारी न्यायालय परिसर के केंद्रीय चेंबर से काम किया है, इसलिए उनके बेटे के लिए ऐसा करना भी संभव होगा। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि मकान मालिक की ओर से कोई सद्भावनापूर्ण आवश्यकता नहीं थी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष अन्य दलीलें उठाई गई थीं, लेकिन उन्हें यहां इस रूप में वर्णित नहीं किया जा रहा है (क) उन प्रतिविरोधों के निष्कर्षों को किरायेदार द्वारा इस याचिका में इस न्यायालय के समक्ष

विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई है, और (ख) निष्कर्ष, इस न्यायालय की राय में, कानून के अनुसार हैं।

4. विद्वान अति.कि.नि. ने किरायेदार की प्रतिविरोधों पर विचार करने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ यह माना कि मकान मालिक वास्तव में न्यायालय में दोषरहित आया है क्योंकि उसने दूसरी दुकान की उपलब्धता को स्वीकार किया है और यह भी बताया है कि दूसरी दुकान की उपलब्धता के बावजूद वाद संपत्ति की आवश्यकता क्यों है। विद्वान अति.कि.नि. ने तर्क दिया कि मकान मालिक की यह इच्छा कि वह वादग्रस्त संपत्ति और उसके साथ लगी खाली दुकान को मिलाकर एक बड़ा स्थान बनाए, जिससे चैंबर का संचालन किया जा सके, उचित, युक्तिसंगत और उसके विशेषाधिकार के अंतर्गत है और किरायेदार द्वारा मकान मालिक पर यह आग्रह करना उचित नहीं होगा कि चैंबर का संचालन एक छोटे क्षेत्र में किया जाए। तार्किक रूप से, विद्वान एआरसी ने अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रतिविरोध कि मकान मालिक के बेटे को तीस हजारी न्यायालय परिसर के सेंट्रल हॉल से काम करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, जिस तरह से उसके पिता ने किया था, उस आधार पर बचाव के लिए अनुमति देने के लिए गुणागुण रहित और अयोग्य है।

5. तदनुसार, बचाव की अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था जिसे इस याचिका में आक्षेपित किया गया है।
6. हालाँकि, इस न्यायालय के समक्ष, किरायेदार ने कुछ नए तथ्यों/आधारों को उठाने की मांग की है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि मकान मालिक के पास पहले से ही एक चेंबर है, जिसे उसे रोहिणी जिला न्यायालयों में आवंटित किया गया है और इस तथ्य को विद्वान अति.कि.नि. से यह कहकर दबाया गया है कि उसके पास कोई भी चेंबर नहीं है। इस संबंध में, किरायेदार ने इस न्यायालय के समक्ष रोहिणी न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा जारी एक सूची की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसमें सदस्यों को चेंबरों के आवंटन के लिए पात्र नहीं ठहराया गया था। इस सूची में यह प्रतिवाद देने के लिए विशेष निर्भरता रखी गई थी कि यह इंगित करता है कि मकान मालिक को वास्तव में रोहिणी जिला न्यायालयों द्वारा एक चेंबर आवंटित किया गया था। याचिका में यह भी प्रतिवाद किया गया है कि वाद संपत्ति से सटी दुकान अधिवक्ता का चेंबर चलाने के लिए अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि यह वाद संपत्ति की तुलना में अधिक चौड़ी सड़क पर है और इसलिए मकान मालिक की आवश्यकता सद्भावनापूर्ण नहीं है। अतिरिक्त आधारों जिन्हें उठाया गया था उनमें शामिल हैं: (क) इस बारे में स्पष्टीकरण की कमी कि मकान मालिक के बेटे ने 2012 तक वाद संपत्ति या आसपास की संपत्ति

से अपना चेंबर शुरू करने की कोशिश क्यों नहीं की, भले ही वह 2004 से अभ्यास कर रहा था, और (ख) इस बारे में स्पष्टीकरण की कमी कि मकान मालिक का बेटा-जो कथित तौर पर आज तक अपने बड़े भाई के चेंबर से अभ्यास कर रहा है-को अब अपने चेंबर से बाहर अभ्यास करने की आवश्यकता होगी।

7. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अग्रिम सूचना पर उपस्थित होकर निवेदन किया कि याचिका में दिए गए आधार तुच्छ एवं निराधार हैं तथा किसी भी स्थिति में विद्वान अति.कि.नि. द्वारा विचार किया जा चुका है तथा निर्णय लिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अब किरायेदार जिस दस्तावेज पर भरोसा करना चाहता है - रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी की गई सूची - वह विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष नहीं थी और इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, सूची से यह संकेत नहीं मिलता है कि मकान मालिक के पास किसी भी चेंबर का कब्जा है। उन्होंने दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी का तीस हजार न्यायालय में कोई चेंबर नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को प्रमाण पत्र की एक प्रति भी सौंपी गयी है। उन्होंने दोहराया कि मकान मालिक के पास

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कहीं भी अपने बेटे की कानूनी अभ्यास की सुविधा के लिए कोई अन्य चैंबर या कार्यालय नहीं है।

8. यह सुस्थापित विधि है कि यह न्यायालय, अधिनियम की धारा 25-बी के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य करता है, न कि अपील न्यायालय के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान के तहत अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर पूर्ववर्ती प्राधिकारियों के मूल्यांकन के बाद शिव सरूप गुप्ता बनाम महेश चंद गुप्ता (डॉ), (1999) 6 एससीसी 222 के मामले में यह निर्णय दिया:

“प्रावधान का वाक्यांश जैसा कि पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 का मसौदा तैयार करने में विधायिका द्वारा नियोजित वाक्यांश के साथ एक दिलचस्प पठन प्रदान करता है। बाद के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन त्रुटियों में से एक को करने के लिए सीमित किया जाता है, अर्थात् (i) कानून द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करना, या (ii) इस तरह से निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहना, या (iii) अवैधता या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना। धारा 25-ख की उप-धारा (8) के प्रावधान के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाली अभिव्यक्ति "संतुष्ट करने के उद्देश्य से है यदि नियंत्रक द्वारा दिया गया आदेश

कानून के अनुसार है"। धारा 25-ख (8) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनरीक्षण संबंधी अधिकार क्षेत्र उतनी सीमित नहीं है जितनी कि सि.प्र.स. की धारा 115 के तहत है और न ही उतनी व्यापक है जितनी कि अपील न्यायालय है। उच्च न्यायालय केवल इसलिए साक्ष्य की सराहना या पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है क्योंकि वह तथ्यों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक है जैसे कि वह तथ्यों का न्यायालय हो। हालाँकि, उच्च न्यायालय किराया नियंत्रक के आदेश को "क्या यह कानून के अनुसार है" की कसौटी पर परखने के लिए बाध्य है।

उस सीमित उद्देश्य के लिए वह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, अर्थात् यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किराया नियंत्रक द्वारा लिया गया निष्कर्ष पूरी तरह से अनुचित है या ऐसा है कि कोई भी उचित व्यक्ति उपलब्ध सामग्री पर निष्पक्षता से कार्य नहीं कर सकता था। साक्ष्य के भार को नजरअंदाज करना, कानून के गलत आधार पर आगे बढ़ना या स्थापित तथ्यों से इस तरह का निष्कर्ष निकालना कि प्रतिवाद की कमी और/या वस्तुनिष्ठता के साथ विश्वासघात करना नियंत्रक के निष्कर्ष को "कानून के अनुसार नहीं" अधिनियम की धारा 25-ख की उप-धारा (8) के प्रावधान के तहत हस्तक्षेप का आह्वान करेगा। न्याय को विफलता की ओर ले जाने वाला निर्णय कानून के अनुसार निर्णय नहीं है। (देखिए: सरला आहूजा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(1998) 8 एससीसी 119] और राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी [(1999) 1 एससीसी 141]।)"

(जोर दिया गया)

9. अपील न्यायालय नहीं होने के कारण, यह न्यायालय इस स्तर पर नए साक्ष्य पर विचार नहीं कर सकता है जो विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष नहीं था। जिस दस्तावेज़ को अब इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई थी, यानी, रोहिणी न्यायालय बार एसोसिएशन की सूची, विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष नहीं थी। इसके विपरीत, किरायेदार ने विद्वान अति.कि.नि. के समक्ष प्रकथन किया है कि, उसकी जानकारी के अनुसार, मकान मालिक केंद्रीय चेंबर, तीस हजारी न्यायालय से बाहर वकालत कर रहा था। इसे देखते हुए, यदि न्यायालय अब उक्त दस्तावेज़ के आधार पर इस याचिका पर निर्णय लेता है तो यह अधिनियम की धारा 25-ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं होगा। किसी भी मामले में, दस्तावेज़ केवल यह इंगित करता है कि मकान मालिक रोहिणी न्यायालय परिसर में एक चेंबर आवंटित करने के लिए अयोग्य है और इसका कारण "रोहिणी में वकालत नहीं करना, पहले से ही चेंबर होना" बताया गया है। यह देखते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि मकान मालिक रोहिणी न्यायालय में वकालत नहीं करता है, यह समझने योग्य है कि वह वहां एक चेंबर के आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा-कुछ ऐसा जो दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से बताता है। इस दस्तावेज़ को इस न्यायालय द्वारा अनदेखा किया जाना चाहिए क्योंकि

इस तथ्य के देखते हुए कि वाद संपत्ति मकान मालिक के बेटे के लिए आवश्यक बताई गई है न कि उसके लिए। इसे देखते हुए, यह न्यायालय उक्त दस्तावेज़ पर गौर नहीं कर सकता।

10. विद्वान अति.कि.नि. द्वारा चुनौती के अन्य आधारों पर पहले ही विस्तार से विचार किया जा चुका है। विद्वान अति.कि.नि. ने, वास्तव में, इस संबंध में एक कारण युक्त आदेश दिया है और अभिनिर्धारित किया है कि यह मकान मालिक का एक सद्भावनापूर्ण अनुरोध है, जो उचित और उसके विशेषाधिकार के भीतर है। मैंने पहले ही 2014 के कि.नि.पु.6 में विस्तार से बताया है कि यह न्यायालय अधिनियम की धारा 25-ख के तहत अपने अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथ्यों का पता लगाने के संबंध में सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे करता है। यह मुद्दा कि क्या मकान मालिक के कब्जे में मौजूद दूसरी संपत्ति, वाद संपत्ति से अधिक उपयुक्त है और क्या मकान मालिक की मांग वास्तविक है, ऐसे तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिन पर यह न्यायालय हस्तक्षेप करने से प्रविरत रहना चाहेगा। इस न्यायालय को जो कुछ भी करने के लिए अनिवार्य किया गया है, वह खुद को संतुष्ट करने के लिए है कि क्या आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है - अर्थात्, क्या यह निष्कर्ष कि मकान मालिक की आवश्यकता वास्तविक है, कानून के अनुसार एक निष्कर्ष है।

11. इस मुद्दे पर जब मकान मालिक की आवश्यकता को सद्भावपूर्वक माना जा सकता है, शिव सरूप गुप्ता (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है:

"13. चेम्बर्स 20वीं शताब्दी शब्दकोष में बोनाफाइड का अर्थ है "सद्भावपूर्वक: वास्तविक"। वास्तविक" शब्द का अर्थ है "प्राकृतिक: नकली नहीं है: वास्तविक:शुद्ध:ईमानदार "। विधि शब्दकोष में, मोजले और व्हिटली ने प्रामाणिक को "सद्भावपूर्व, कपट या प्रवंचना के बिना" के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार, सद्भावना या वास्तविक शब्द मन की स्थिति को संदर्भित करता है। आवश्यकता मात्र एक इच्छा नहीं है। "आवश्यकता" द्वारा अपेक्षित की गई तीव्रता की मात्रा केवल इच्छा की तुलना में बहुत अधिक है। वाक्यांश "आवश्यक सद्भावना" विधायी मंशा का सूचक है कि मात्र इच्छा जो सनक या कल्पना का परिणाम है, किराया नियंत्रण विधान द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। महसूस की गई आवश्यकता के अर्थ में आवश्यकता, जो एक ईमानदार, सच्ची इच्छा का परिणाम है, किरायेदार को बेदखल करने के महज बहाने या बहाने के विपरीत, मकान मालिक द्वारा स्वयं के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए परिसर पर कब्जा करने का दावा करने पर उसे किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मकान मालिक की आवश्यकता और उसकी सद्भावना को उजागर करने वाले तथ्यों और परिस्थितियों का कोई भी विन्यास न्यायालय द्वारा वस्तुनिष्ठ निर्धारण की कसौटी पर सफलतापूर्वक खरा उतरने में सक्षम होगा। तथ्यों के न्यायाधीश को

स्वयं को मकान मालिक की कुर्सी पर बिठाना चाहिए और फिर स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए - क्या मकान मालिक द्वारा प्रमाणित तथ्यों के आधार पर परिसर पर कब्जा करने की आवश्यकता को स्वाभाविक, वास्तविक, ईमानदार, सद्भावपूर्वक कहा जा सकता है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो आवश्यकता सद्भावनापूर्वक है। मकान मालिक की ओर से निवेदन की गई आवश्यकता को साबित करने में विफलता, या किसी दिए गए मामले में, किरायेदार द्वारा अभिलेख पर लाई गई सकारात्मक सामग्री न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम बनाती है कि वास्तविकता इसके विपरीत थी और मकान मालिक केवल किरायेदार से छुटकारा पाने के लिए एक ढोंग या बहाने रचने का प्रयास कर रहा था, न्यायालय को निश्चित रूप से मकान मालिक को अपनी न्यायिक सहायता से इनकार करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त होगा।”

(जोर दिया गया)

12. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले बताया गया है, कि विद्वान अति.कि.नि. ने अभिनिर्धारित किया है कि मकान मालिक की आवश्यकता - यानी, उसे अपने बेटे के लिए एक चैंबर बनाने के उद्देश्य से वाद संपत्ति की आवश्यकता है - जो कि कानून का अभ्यास कर रहा है - सद्भावनापूर्ण और प्रमाणिक है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मकान मालिक के लिए यह उचित है कि वह न केवल वर्तमान में उपलब्ध - लेकिन छोटी - दुकान का उपयोग करे, बल्कि वाद संपत्ति का भी उपयोग करे, ताकि एक बड़ा स्थान बनाया जा सके, जिसमें से चैंबर

का संचालन किया जा सके। इस पर न्यायालय ने पाया कि यह एक बार फिर शिव सरूप गुप्ता (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार है, जहां यह अनुपालन किया गया कि ,

“किराया नियंत्रण कानून का यह इरादा नहीं हो सकता था कि मकान मालिक को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में एक अलग घर और इलाके में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाए ताकि किरायेदार को किरायेदार के परिसर में रहने की अनुमति दी जा सके। यदि मकान मालिक अपने स्वयं के घर में आराम से रहना चाहता है, तो कानून उसे किरायेदार के कब्जे की रक्षा करते हुए खुद को छोटे परिसर में जकड़कर रहने के लिए आदेश नहीं देता या मजबूर नहीं करता है।”

(जोर दिया गया)

13. यहां तक कि यह निष्कर्ष कि वर्तमान में उपलब्ध परिसर उसके आकार और मकान मालिक के बेटे के कथित पेशे को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा-जिसके लिए वाद संपत्ति की आवश्यकता बताई गई है - जैसा कि यह *एम. एल. प्रभाकर बनाम राजीव सिंघल*, (2001) 2 एस.सी.सी. 355 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रतिकूल नहीं है, जहां, इस संबंध में पूर्व अधिकारियों को ध्यान में रखने के बाद, जिसमें *प्रतिभा देवी बनाम टी.वी. कृष्णन*, (1996) 5 एस.सी.सी. 353,

राम नारायण अरोड़ा बनाम आशा रानी, (1999) 1 एस.सी.सी. 141 और

शिव सरूप गुप्ता (पूर्वोक्त) शामिल हैं। अभिनिर्धारित किया गया:

“8. इस प्रकार यह देखा जाना चाहिए कि उपयुक्तता को मकान मालिक और उसके परिवार के सदस्यों की सुविधा से और उनके पेशे, व्यवसाय, जीवन शैली, आदतों और पृष्ठभूमि सहित परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर देखा जाना चाहिए।”

14. यह समझने योग्य है कि एक कमरा जो केवल 6 'x 10' है, विधि चेंबर के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हालांकि, अगर मकान मालिक चाहता है कि उसे मकान मालिक के दूसरे आस-पास के परिसर से अलग करने वाली दीवार को हटाकर बढ़ाया जा सके, ताकि इसका क्षेत्र 12'x 10.3' तक बढ़ाया जा सके, तो यह अभ्यास करने के लिए एक कार्यालय/चेंबर स्थापित करने के लिए उचित मात्रा में जगह प्रदान कर सकता है।
15. उपरोक्त को देखते हुए, यह न्यायालय अधिनियम की धारा 25 ख के तहत अपनी अधिकारिता के प्रयोग करते हुए इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाता है ।
16. उपरोक्त कारणों से, मामले को खारिज कर दिया जाता है।

नजमी वज़ीरी
(न्यायाधीश)

06 ,जनवरी,2014

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।